University in News on 24 September 2024

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

सेंटर फॉर एक्सीलेंस में लविवि का दबदबा

योजना में विवि के 20 शिक्षकों के शोध प्रस्ताव चयनित, सरकार ने दिया 1.52 करोड़ रुपये का अनुदान

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। सेंटर फॉर एक्सीलेंस योजना में लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षको ने दबदबा कायम किया है। विवि के 20 शिक्षकों के शोध प्रस्ताव सरकार की इस योजना के तहत चयनित किए गए हैं। इसके लिए शिक्षकों को कुल 1.52 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इससे वे अपने विभाग में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कर छात्रों से संबंधित विभिन्न शैक्षिक कार्य पूरे कर पाएंगे।

प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत सर्वाधिक प्रस्ताव लविवि के शिक्षकों के स्वीकृत किए गए हैं। यह विवि के लिए गौरव की बात है। लविवि निरंतर शोध और नवाचार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यही वजह है कि यहां के शिक्षक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा बिखेर रहे हैं।

विवि में दो विभागों को सर्वाधिक पांच-पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिले हैं। इन विभागों में प्राणि और वनस्पति विज्ञान शामिल हैं।

इसी तरह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विवि के भी पांच शिक्षकों डॉ. रुचिता चौधरी, डॉ. राहुल मिश्रा, डॉ. दोआ नकवी, प्रो. चंदना डे, प्रो. मसूद फलाही के प्रस्तावों का चयन किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत चयनित प्रस्तावों और उनके लिए स्वीकृत अनुदान की सूचना विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने कुलसचिव और वित्त अधिकारी को पत्र भेजकर दे दी है।

लविवि को मिला सर्वाधिक अनुदान

सेंटर फॉर एक्सीलेंस योजना के तहत सरकार की ओर से निर्धारित बजट में सर्वाधिक धनराशि लविवि के 20 शिक्षकों के प्रस्तावों को आवंटित की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत सत्र 2024-25 के लिए मंजूर किए गए कुल 3.88 करोड़ रुपये में 1.52 करोड़ लविवि को मिले हैं। वहीं, शेष धनराशि अन्य सात राज्य विवि के शिक्षकों मिली है।

विधि विवि के तीन शिक्षकों को भी मिला लाभ

लोहिया विधि विश्वविद्यालय के तीन शिक्षकों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए अनुदान मिला है। इनमें अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर डॉ. अलका सिंह, विधि विभाग की डॉ. अपर्णा सिंह व डॉ. मनोज कुमार शामिल हैं।

विभागवार शिक्षकों को मिली राशि

- प्रो. शैली मलिक-प्राणि विज्ञान - 4 लाख
- प्रो. गीतांजलि मिश्रा-प्राणि विज्ञान -3.60 लाख
- प्रो. संगीता रानी-प्राणि विज्ञान - 6.58 लाख
- डॉ. मनोज कुमार-प्राणि विज्ञान - 14.50 लाख
- डॉ. राजेश कुमार-प्राणि विज्ञान - 3.20 लाख
- डॉ. गिरीश पाठक-वनस्पति विज्ञान - 8.60 लाख
- डॉ. अमित सिंह-वनस्पति विज्ञान - 6.10 लाख
- डॉ. सुषमा मिश्रा-वनस्पति विज्ञान - 8.65 लाख
- डॉ. प्रदीप मिश्रा-वनस्पति विज्ञान - 7.15 लाख
- प्रो. मो. इस्त्रायल-वनस्पति विज्ञान - 2.50 लाख
- डॉ. आंचल-भौतिक विज्ञान - 14.40 लाख
- प्रो. नीरज मिश्रा-भौतिक विज्ञान - 6.95 लाख
- डॉ. आरके शुक्ला-भौतिक विज्ञान - 14.25 लाख
- प्रो. सिद्दार्थ मिश्रा-बायोकेमिस्ट्री - 10.15 लाख
- प्रो. अनूप भारतीय-समाजकार्य - 4.90 लाख
- डॉ. रवींद्र प्रताप सिंह-अंग्रेजी - 5.90 लाख
- डॉ. विनीता काचर-विधि - 7.40 लाख
- डॉ. अशोक कुमार सिंह-केमिस्ट्री - 6.40 लाख
- डॉ. राकेश कुमार सिंह-विधि - 3.40 लाख
- डॉ. नरेंद्र कुमार पांडेय-फिजिक्स- 14.20 लाख

शिक्षा | कॉलेजों में दाखिले की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय

निरीक्षण के साथ ही होगी कॉलेजों की रैंकिंग

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय सभी कॉलेजों की रैंकिंग करेगा। इसके साथ ही नियमित निरीक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। अमर उजाला के अभियान के बाद लविवि ने कॉलेजों में नाममात्र के दाखिले को लेकर रणनीति बनाई है। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के मुताबिक दाखिलों की संख्या बढ़ाने के लिए गुणवत्ता में सुधार सबसे जरूरी है।

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान पटरी से उतरा सत्र इस बार वापस नियमित हो गया है। अब हमारे पास कॉलेजों में सुधार करने का मौका है। इसके तहत कॉलेजों का निरीक्षण कर पढ़ाई की स्थिति देखी जाएगी। यदि किसी कॉलेज में कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो इस पर मंथन करने की जरूरत है। कॉलेज प्रशासन को नियमित कक्षाएं चलानी हैं। यदि वे कम दाखिलों की वजह से कक्षाएं नहीं संचालित कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सभी कॉलेजों की रैंकिंग की जाएगी। यह रैंकिंग कोर्सवार, सरकारी और गैरसरकारी श्रेणी में हो सकती है। इसके पैरामीटर तय किए जा रहे हैं।

नए कॉलेजों व कोर्स के बावजूद कम हो गए 14 फीसदी विद्यार्थी

बीलिब और बीएलएड में विद्यार्थियों का टोटा

लविवि से जुड़कर कॉलेजों में 28 फीसदी तक घटे दाखिले

सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और रायबरेली के कॉलेजों का बुरा हाल

शिक्षक करें मंथन, क्यों नहीं हो रहे दाखिले

कुलपति के मुताबिक जहां-जहां दाखिले नहीं हो रहे हैं, वहां के शिक्षकों को इस पर विचार करना चाहिए। लविवि के ज्यादातर पाठ्यक्रमों को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। कुछ कोर्स में दाखिले कम हुए हैं, वहां समीक्षा की जरूरत है। वहीं, जिन कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए।

एक्सेल शीट में वेबसाइट पर पड़ेगी शिक्षकों की सूची

कॉलेजों में अयोग्य शिक्षकों के भरोसे कक्षाएं संचालन को भी लविवि प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कुलपति के मुताबिक सभी स्थायी मान्यता वाले निजी और सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सूची एक्सेल शीट पर उनकी फोटो के साथ वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इससे दोहरे अनुमोदन और फर्जी शिक्षकों की समस्या दूर होगी। विद्यार्थी और उसके माता-पिता को भी पता होगा कि जिस शिक्षक का नाम वेबसाइट पर है, उनको वही पढ़ा रहा है।

नौकरीपेशा लोग एमबीए के लिए 30 तक करें आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने नौकरीपेशा लोगों को प्रबंधन की शिक्षा देने के लिए पहली बार एग्जीक्यूटिव एमबीए का कोर्स शुरू किया है। इसमें प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक विवि की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। दाखिले मेरिट के आधार पर होंगे। किसी भी जानकारी के लिए डीन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

मेरिट के आधार पर होंगे दाखिले

प्रबंधन संकाय की डीन प्रो. संगीता साहू ने बताया कि विवि ने बताया कि यह दो वर्षीय डिग्री कोर्स यूजीसी के ब्लेंडेड मोड (मिश्रित शिक्षा) में संचालित होगा। इसका उद्देश्य शिक्षण के लिए आमने सामने की कक्षा विधियों को कंप्यूटर मध्यस्थता गतिविधियों के साथ जोड़ना है। इसमें पारंपरिक और ऑनलाइन शिक्षण विधियों के फायदों को मिलाकर विद्यार्थियों को अधिक रोचक तरीके पढ़ाना होता है।

कोर्स का प्रत्येक सेमेस्टर 24 क्रेडिट का होगा। इसके तीसरे सेमेस्टर में विद्यार्थी को स्पेशलाइजेशन चुनने का अवसर दिया जाएगा। विद्यार्थी ह्यूमन रिसोर्स (एचआर), मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस (आईबी) को बतौर स्पेशलाइजेशन कोर्स चुन सकेंगे।

ऑनलाइन व ऑफलाइन चलेंगी कक्षाएं

प्रो. संगीता साहू ने बताया कि कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की 60 फीसदी कक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि 40 फीसदी कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। ऑफलाइन कक्षाएं उनकी सुविधानुसार वीकेंड में रखी जाएंगी। कोर्स की फीस प्रतिवर्ष 99800 रुपये तय की गई है।

अंतर्विभागीय शोध की दिशा में बढ़ाएं कदम

लखनऊ। शोध का आधार डेटा है। डेटा के तीन रूप हैं, पहला लिखित, दूसरा छवि एवं तीसरा मौखिक। शोधार्थी को स्रोतों का अध्ययन करते समय सावधानी रखना चाहिए। ये बातें लविवि के पूर्व प्रति कुलपति प्रो. अरविंद अवस्थी ने कही। वह सोमवार विवि के उर्दू विभाग के संयोजन में चल सात दिवसीय शोध कार्यशाला के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। दूसरे सत्र के वक्ता प्रो. शमा महमूद ने कहा कि शोधार्थियों को अंतर्विभागीय शोध की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। (संवाद)

लविवि : खाने के समय मेस में मौजूद रहेंगे शिक्षक

लखनऊ। लविवि के छात्रावासों की मेस में दोपहर व रात के खाने के समय शिक्षक, प्रोवोस्ट या उनकी टीम का कोई सदस्य मौजूद रहेगा। खाने की गुणवत्ता बनाए रखने व उपद्रव रोकने के लिए यह पहल की गई है। रविवार देर रात एलयू के सुभाष हॉस्टल में खाने को लेकर विवाद के बाद यह कदम उठाया गया है। (संवाद)

VoL PAGE 6

लविवि के 20 और भाषा विवि के पांच शिक्षकों को मिली प्रोजेक्ट ग्रांट

लखनऊ। उच्च शिक्षा परिषद की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय के 20 शिक्षकों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए प्रोजेक्ट ग्रांट दी गयी है। वहीं भाषा विश्वविद्यालय के पांच शिक्षकों को भी प्रोजेक्ट ग्रांट दी गयी है। इसमें प्रो मसूद आलम, अरबी विभाग, प्रो. चंदना डे, शिक्षा शास्त्र विभाग, डॉ रुचिता सुजय चौधरी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, डॉ दोआ नकवी, व्यवसाय प्रबंधन विभाग, डॉ राहुल कुमार, अर्थशास्त्र विभाग को सेंटर फॉर एक्सिलेंस योजना के अंतर्गत कुल रु. 21,20,000 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। कुलपति प्रो एनबी सिंह ने पांचो शिक्षकों को बधाई देते हुए आशा जताई है कि इस आर्थिक सहयोग की धनराशि के सदुपयोग से विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।

HINDUSTAN PAGE 8

एलयू: बीफार्मा की काउंसलिंग 27 को

लखनऊ। एलयू में बीफार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 27 सितंबर को होगी। वह अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पंजीकरण कराया है।

प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव का कहना है कि काउंसलिंग 27 सितम्बर को नवीन परिसर, इंजीनियरिंग संकाय में सुबह नौ बजे से होगी। जिन्होंने पंजीकरण कराया हैं, वे रिपोर्ट करें। बीफार्मा की फीस 66,100 रुपये तय है। पंजीकरण शुल्क एक हजार और कॉशन मनी पांच हजार जमा होगा।

एलयू के 20 शिक्षकों को डेढ़ करोड़ अनुदान मिला

उपलब्धि

- प्रदेश के 58 शिक्षकों को अनुदान, लखनऊ के 29 शिक्षक शामिल

लखनऊ, संवाददाता। एलयू के 20 शिक्षकों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रोजेक्ट के लिए अनुदान दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव की ओर से प्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया गया है। जिसमें यूपी के 58 शिक्षकों को 3.88 करोड़ का अनुदान मिला है। एलयू के 20 शिक्षकों को 1.52 करोड़ मिले हैं।

एलयू शिक्षकों में प्राणिशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉ. गीतांजलि मिश्रा को 3.60 लाख, प्रो. शैली मलिक को चार लाख, डॉ. राजेश कुमार खरवार को 3.20 लाख डॉ. मनोज कुमार को 14.5 लाख समेत अन्य को अनुदान मिला है।

भाषा के छह शिक्षकों को अनुदान केएमसी भाषा विश्वविद्यालय के छह शिक्षकों ने पच्चीस लाख सत्तर हजार का अनुदान प्राप्त किया है।

लोहिया के तीन शिक्षकों को ग्रांट: लोहिया विधि विवि के तीन शिक्षकों को प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मिली है।

JAGRAN CITY PAGE III

29 शिक्षकों के प्रोजेक्ट को मिलेंगे 1.88 करोड़

लवि व भाषा विश्वविद्यालय में सेंटर आफ एक्सीलेंस के तहत शोध को मिलेगा बढ़ावा

जागरण संवाददाता • लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय और डा.राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में सेंटर आफ एक्सीलेंस के तहत शोध के लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसमें विश्वविद्यालय के 29 शिक्षकों के प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ 88 लाख रुपये से अधिक धनराशि मिलेगी। यह फंडिंग विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित की गई है, जिससे शिक्षक अपनी अनुसंधान परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे। इससे राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय के 20 शिक्षकों को एक करोड़ 52 लाख से अधिक का अनुदान: लखनऊ विश्वविद्यालय के 20 शिक्षकों को एक करोड़ 52 लाख 82 हजार से अधिक के शोध प्रोजेक्ट मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 14 लाख 50 हजार रुपये की राशि जूलाजी के डा. मनोज कुमार, फिजिक्स के प्रो. नरेंद्र कुमार पांडेय को 14,20,000 रुपये और डा. अंचल श्रीवास्तव को 14,40,000 रुपये की मंजूरी मिली है। इस शोध प्रोजेक्ट के अनुसार शिक्षक स्वदेशी हर्बल एंटीकैंसर थेरेपी पर ट्रांसलेशनल रिसर्च, बाल अधिकार शिक्षा : उत्तर प्रदेश में बाल श्रम को समाप्त करने का रोडमैप, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में लोक साहित्य, लेडीबर्ड बीटल के संवर्धन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कृषि सहित कई विषयों पर शोध करेंगे। इसके लिए जंतु विज्ञान की प्रो. गीताजंलि मिश्रा को 3,60,000 रुपये, डा. मनोज कुमार 14,50,000 रुपये, प्रो. शैली मलिक 4,00,000 रुपये, डा. राजेश कुमार खरवार को 3,20,000 रुपये, प्रो. संगीता रानी को 6,57,800 रुपये, वनस्पति विज्ञान विभाग के डा. गिरीश चंद्र पाठक को 8,60,000 रुपये, डा. अमित कुमार सिंह को 6,10,000 रुपये, डा. सुषमा मिश्रा को 8,65,000 रुपये, डा. प्रदीप कुमार को 7,15,000 रुपये, प्रो. मोहम्मद इसराइल अंसरी को 2,50,000 रुपये, भौतिक विज्ञान में प्रो. नरेंद्र कुमार पांडेय को 14,20,000 रुपये, डा. अंचल श्रीवास्तव को 14,40,000 रुपये, प्रो. नीरज मिश्रा को 6,95,000 रुपये, डा. आरके शुक्ला को 14,25,000 रुपये, बायोकेमिस्ट्री प्रो. सिद्धार्थ कुमार मिश्रा को 10,15,000 रुपये, सोशल वर्क प्रो. अनूप कुमार भारतीय को 4,90,000 रुपये, अंग्रेजी में प्रो. रवींद्र प्रताप सिंह को 5,90,000 रुपये, विधि में प्रो. विनीता काचर को 7,40,000 रुपये, प्रो. राकेश कुमार सिंह को 3,40,000 रुपये, केमिस्ट्री में डा. अशोक कुमार सिंह को 6,40,000 रुपये है।

विधि विश्वविद्यालय के तीन शिक्षकों को 12 लाख का अनुदान

डा. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की सहायक प्रो. अलका सिंह को मानवाधिकार व अंग्रेजी साहित्य अध्ययन (अनुसंधान प्रयोगशाला और स्मार्ट उपकरणों का विकास) के लिए चार लाख रुपये, विधि के सहायक प्रो. मनोज कुमार को ई-कामर्स की कार्य-प्रणाली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे व चिंताएं के लिए तीन लाख 30 हजार रुपये और विधि की सहायक प्रो. अपर्णा सिंह को माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में मानवाधिकार अध्ययन/शिक्षा की स्थिति पर अध्ययन के लिए चार लाख 85 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

भाषा विश्वविद्यालय के छह शिक्षकों को 24 लाख से अधिक का अनुदान

भाषा विश्वविद्यालय के अरबी विभाग के प्रो. मसूद आलम को समकालीन अरब लेखन में भारतीय संस्कृति के प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए तीन लाख 90 हजार रुपये, व्यवसाय प्रशासन विभाग के सहायक प्रोफेसर दोआ नकवी को चार लाख रुपये, अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रो. राहुल मिश्रा को सरकारी और निजी संस्थानों में मानवीय मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता के प्रति धारणा का तुलनात्मक अध्ययन के लिए चार लाख 90 हजार रुपये, पत्रकारिता विभाग की सहायक प्रो. रुचिता सुजाय को संचार और आडियो विजुअल उत्कृष्टता केंद्र के लिए चार लाख रुपये, भूगोल विभाग के एसोसिएट प्रो. प्रवीण राय को शहरी विस्तार और भूमि कवर स्पैशन-टेम्पोरल गतिशीलता का अध्ययन के लिए चार लाख रुपये, शिक्षा विभाग के प्रो. चंदना डे को कुकरैल नदी वाटरशेड का उपयोग रिमोट सेंसिंग और जीआइएस के माध्यम से अध्ययन के लिए चार लाख 40 हजार रुपये का अनुदान मिला है।

एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए खुला एलयूआरएन पोर्टल

लखनऊ : लवि के प्रबंधन विभाग में इसी सत्र से एग्जीक्यूटिव एमबीए पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने इस कोर्स में आवेदन फार्म भरने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर (एलयूआरएन) पोर्टल सोमवार को खोल दिया है। अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने बीते 20 सितंबर को एलयूआरएन पोर्टल बंद कर दिया था। अब सिर्फ एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए के लिए पंजीकरण का मौका दिया गया है। कोर्स में आवेदन के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ-साथ इंडस्ट्री में काम करने का दो साल का अनुभव जरूरी है। (जासं)

बीफार्म की काउंसिलिंग 27 सितंबर को

जासं • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार बीफार्म पाठ्यक्रम में दाखिले सीयूईटी की मेरिट से लेगा। इसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन लिए जा चुके हैं। 27 सितंबर को सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक आवेदकों की काउंसिलिंग कर अभिलेखों का सत्यापन होगा। उसके बाद मेरिट के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपनी लागइन पर देखकर दोपहर दो बजे के बाद फीस जमा कर सकेंगे। बी.फार्म कोर्स में 100 सीटों पर प्रवेश होंगे। सोमवार को प्रवेश समन्वयक डा. अनित्य गौरव ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। प्रवेश समन्वयक ने बताया कि बी.फार्म में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 27 सितंबर को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। उसी दिन उपलब्ध सीटों के सापेक्ष सीयूईटी की मेरिट के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी लागइन पासवर्ड के माध्यम से द्वितीय परिसर के इंजीनियरिंग संकाय में बने काउंसिलिंग सेंटर पर आनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल अभिलेखों एवं उसकी एक प्रतिहस्ताक्षरित कापी लेकर आना है।